



‘हर खिलाड़ी समाज का हीरो, राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा : सीएम योगी’

-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उनकी स्मृतियों को किया नमन
-सीएम बोले- खेल जीवन का अनुशासन, समन्वय और टीमवर्क प्रज्वलित करता है राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना
-हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हो रही स्थापना : सीएम
-ग्राम पंचायत से जनपद स्तर तक प्रदेश सरकार कर रही खेल अवसरचरणा का विस्तार : मुख्यमंत्री
-खेल दिवस पर सीएम योगी ने 88 पदक विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान
-कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहायक खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र
-विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण का किया लोकार्पण

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हुए कहा कि हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए एक हीरो होता है। हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ने, खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता उत्तर प्रदेश के 88 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की और सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। समारोह में खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों सहित नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण का लोकार्पण भी किया।

‘मेजर ध्यानचंद को नमन’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है तो हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है। 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में

स्वर्ण पदक दिलाकर उन्होंने भारत की हॉकी को वैश्विक पहचान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार किसी नेता नहीं, बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए यह इसलिए भी गौरव की बात है क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि है। उनकी स्मृति में मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किया गया है और इस सत्र से वहां पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है।

‘खेलों में नई क्रांति की शुरुआत’

मुख्यमंत्री ने विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाम स्पोर्ट्स कॉलेज का रोमांचक हॉकी मैच भी देखा। उन्होंने कहा कि यह खेल कितना फास्ट है, कितनी ऊर्जा और टीमवर्क मांगता है। यह मैच इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, खेलो इंडिया से फिट इंडिया मूवमेंट तक, सांसद एवं विधायक स्तर की प्रतियोगिताओं तक, देश में खेलों की एक नई क्रांति आई है। प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति लागू की है, जिससे खिलाड़ियों को मंच, कोच और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो रहा है।

‘ग्राम से जनपद तक खेल ढांचा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है। विभिन्न खेलों के लिए इन कॉलेजों में सेंटर ऑफ

एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। पर्व व ओलंपियन/कॉमनवेल्थ/एशियाड/नेशनल गेम्स मेडलिस्टों को कोच बनाकर नई प्रतिभाओं को तलाश जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, हर विकासखंड पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है। ओपन जिम के निर्माण व युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है।

‘युपी की हॉकी विरासत को किया याद’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हॉकी में अनेक दिग्गज दिए हैं। मेजर ध्यानचंद, के. डी. सिंह ‘बाबू’, मोहम्मद शाहिद, रवींद्र पाल, सैयद अली, डॉ. आर. पी. सिंह, सुजीत कुमार, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एम. पी. सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, बंदना कटारिया, रितुषा कुमारी आर्या जैसे हॉकी खिलाड़ियों प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने उत्तर प्रदेश की ही देन हैं।

‘खेल से बनता है सशक्त भारत’

सीएम ने कहा कि खाली दिमाग



‘सीएम योगी ने हॉकी स्टिक उठाई, शॉट लगाया और फिटनेस की शपथ दिलाई’

सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान हॉकी स्टिक से गेंद को हिट करके स्टेड हॉकी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। यही नहीं, उन्होंने कुछ देर तक हॉकी मैच भी देखा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों में सम्मिलित होने और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाई, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को सार्वजनिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन एक खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और खेल के अलौकिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का परिचय भी प्राप्त किया और उनके खेल और पढ़ाई के विषय में भी बात की। मैच के अंत में मुख्यमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

‘पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन’

अपने संबोधन में सीएम योगी ने प्रदेश के खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनिशप, नेशनल स्टेड गेम्स में एकल और टीम गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। उनके अनुसार...

ओलंपिक : एकल-स्वर्ण 6 करोड़, रजत 4 करोड़, कांस्य 2 करोड़; टीम स्वर्ण 3 करोड़, रजत 2 करोड़, कांस्य 1 करोड़।

एशियन गेम्स : स्वर्ण 3 करोड़, रजत 1.5 करोड़, कांस्य 75 लाख।

कॉमनवेल्थ गेम्स : स्वर्ण 1.5 करोड़, रजत 75 लाख, कांस्य 50 लाख।

वर्ल्ड चैंपियनिशप : स्वर्ण 1.5 करोड़, रजत 75 लाख, कांस्य 50 लाख।

नेशनल/स्टेट गेम्स : एकल स्वर्ण 6 लाख, रजत 3 लाख, कांस्य 2 लाख; टीमस्वर्ण 2 लाख, रजत 1 लाख, कांस्य 50 हजार।

प्रतिभाग प्रोत्साहन : ओलंपिक में हिस्सा लेने पर 10 लाख, कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स में प्रतिभाग पर 5-5 लाख।

सम्मानित पुरस्कृत/पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को सहायता : अर्जुन, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद, खेल रत्न व खेल क्षेत्र के पद्म पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को 20,000 प्रतिमाह सहायता।

वृद्ध/अशक्त/विपदाग्रस्त खिलाड़ी : अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 प्रतिमाह वित्तीय सहायता।

‘सीएम योगी ने इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण’

आजमगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में समर्पित छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण पीलीभीत के बहुउद्देशीय क्रीडाहाल एवं प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर वॉलीबाल हॉल का जीर्णोद्धार कार्य बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य बांदा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम उपकरणों की स्थापना का कार्य मऊ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के जीर्णोद्धार कार्य मऊ में सिंथेटिक हॉकी मैदान के निर्माण कार्य का लोकार्पण।

आर्थिक सुधारों की नई पहल, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर नए आर्थिक सुधारों के आह्वान के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने उन अहम क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें निश्चित समय सीमा के भीतर सुधार किए जाएंगे। योजना के तहत खनन और बिजली उत्पादन को दोगुना करने, बड़े निवेश आकर्षित करने, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने, लघु एवं उच्च मॉड्यूलर रिफ़ाइनरी विकसित करने और कोयला गैसीकरण जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य राजीव गांधी करेंगे। समिति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। साथ ही, एक दूसरी समिति गैर-वित्तीय नियामकीय सुधारों पर काम करेगी। यह समिति मौजूदा कानूनों की प्रासंगिकता की समीक्षा करेगी और अनुपालन का बोझ कम करने के लिए स्व-अभिप्रमाणन व तीसरे पक्ष की निगरानी जैसे विकल्पों पर विचार करेगी।

जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत

एजेंसी

तोक्यो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान की दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को तोक्यो पहुंचे जहां वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स पर एक पोस्ट’ में कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के तोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ शाम को व्यापक चर्चा करेंगे।’ अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सम्यक्तागत संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगी। मोदी 29-30 अगस्त को जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा पर कहा, ‘हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी ने पिछले 11 वर्षों में लगातार और महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा, ‘हम अपने सहयोग को नयी उड़ान देने, आर्थिक व निवेश संबंधों के दायरे एवं महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने, कृत्रिम मेधा (एआई) व सेमीकंडक्टर सहित नयी और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जापान से मोदी 31 अगस्त से दो दिवसीय यात्रा पर चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें पूर्वी लहाख सीमा विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा केन्द्रित करने की संभावना है।



बार-बार पाकिस्तान जाने वाले नहीं कर सकते असम का नेतृत्व, अमित शाह ने बोला हमला

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि असम का नेतृत्व ऐसे लोग नहीं कर सकते जो बार-बार पाकिस्तान जाते हैं। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोर्गोई के पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों की ओर इशारा करते हुए कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों की आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए अगले साल मार्च-अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए ‘युद्ध का बिगुल फूँका। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रतिनिधित्व ऐसे नेता नहीं कर सकते जो घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के प्रति सहानुभूति रखते हों। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अनेक विकास कार्य किए हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उस विकास को राज्य के घर-घर तक पहुंचाया है। इन कार्यों की बदौलत, भाजपा के नेतृत्व वाला राजग अगले साल लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगा। विपक्षी कांग्रेस की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि असम का प्रतिनिधित्व घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं कर सकते। गौरव गोर्गोई के संदर्भ में अमित शाह ने कहा, ‘असम का नेतृत्व ऐसे लोग नहीं कर सकते, जो अकसर पाकिस्तान जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोर्गोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला बोलते रहे हैं। शर्मा ने दावा किया था कि गोर्गोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने भारत और पाकिस्तान के बीच 19 बार यात्रा की थी। शाह ने कहा, ‘घुसपैठियों ने हमारी हजायें एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। भाजपा सरकार ने हर जगह से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, लेकिन गौरव गोर्गोई ने इसका विरोध किया... असम सरकार ने घुसपैठियों के अतिक्रमण से 1,29,548 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने घुसपैठियों को बाहर निकालकर श्रीमंत शंकरदेव और महापुरुष माधवदेव के सत्रों (बैथन मठों) की पवित्रता को बहाल किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि असम में भाजपा सरकार ने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया, जो ‘हमारी बैठियों से शादी करते थे। हाल के ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में शाह ने कहा, ‘यदि आप असम पंचायतों में कांग्रेस को दूढ़ना चाहें तो आप उन्हें दूरबीन से भी नहीं दूढ़ पाएंगे।

संपादकीय

कोचिंग की मजबूरी

हाल के दिनों में कोचिंग का तेजी से बढ़ता प्रचलन अभिभावकों के बजट को बिगाड़ रहा है। छात्रों का कोचिंग जाना धीरे-धीरे अपरिहार्य माना जाने लगा है। जिसके चलते माता-पिता को अपने अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। हाल ही में भारत सरकार के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश भर के लगभग हर चार में से एक स्कूली छात्र ने इस वर्ष निजी कोचिंग ली। कुल मिलाकर देश के 27 फीसदी विद्यार्थी निजी कोचिंग लेते हैं। यह प्रतिशत शहरों में ज्यादा है, जो सर्वे में करीब 31 फीसदी पाया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में कम— 25 फीसदी पाया गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में यह कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है बल्कि शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों से अपने बच्चों को उबारकर उनके बेहतर भविष्य की आस का जरिया है। उस स्थिति से उबरने की कोशिश है जो छात्रों को परीक्षा से पूर्व तनाव व परेशानी में धकेल देती है। केंद्र सरकार के व्यापक पारिषद माड्यूलर सर्वेक्षण यानी सीएमएस में खुलासा हुआ है कि शहरी परिवार कोचिंग पर साल में औसतन चार हजार रुपये खर्च करते हैं। वहीं उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिये राशि बढ़कर दस हजार रुपये हो जाती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च कम हो जाता है। लेकिन फिर भी परिवार की आय पर दबाव जरूर बनाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (शिक्षा) के ये आंकड़े एक सच्चाई को उजागर करते हैं कि स्कूली पढ़ाई छात्रों की सभी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाती। यानी स्कूल छात्रों की परीक्षाओं के लिये अपेक्षित आत्मविश्वास प्रदान करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर बात है कि यदि स्कूलों में पढ़ाई छात्राओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हो और उनकी जिज्ञासा कक्षा की पढ़ाई के दौरान शांत हो जाए, तो वे कोचिंग की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। सर्वे बताता है कि आज देश में 56 फीसदी छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या दो दिहाई है। निस्संदेह, ऐसी स्थिति में कोचिंग का बढ़ता प्रचलन आकांक्षाओं से ज्यादा व्यवस्थागत कमजोरी का संकेत है। वहीं पंजाब और हरियाणा में,यह प्रचलन ज्यादा है जहां बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं का अधिक दबाव हावी रहता है। जिसके चलते कुकरमुत्तो की तरह कोचिंग सेंटर उग रहे हैं। नतीजा साफ है कि कक्षाओं में ठीक से पढ़ाई न होने के कारण छात्रों का ध्यान व पैसा स्कूल के समानांतर चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों को जा रहा है। कोचिंग सेंटर, जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा जुटाना ही है, वे समाज में एक कुत्रिम स्पर्धा ट्यूशन पढ़ने व न पढ़ने वाले छात्रों के बीच पैदा कर रहे हैं। पारिवरिक परिस्थितियों के चलते ट्यूशन न पढ़ने वाले छात्र असुरक्षा व हीन भावना के शिकार हो जाते हैं।

दरअसल, इस समस्या का समाधान कोचिंग को बाजार हिस्सा मानकर नहीं किया जा सकता है। प्रतिबंध या सीमाएं निर्धारण से भी समस्या का समाधान करने के बजाय हम इस मुद्दे को और जटिल बना देंगे। बेहतर होगा कि स्कूल में कमजोर छात्रों को स्कूल के समय बाद अतिरिक्त कक्षाओं के जरिये मजबूती प्रदान की जाए। खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे छात्रों पर अधिक ध्यान व समय देकर स्कूल प्रबंधक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। अधिक विषयों के लिये योग्य शिक्षकों की नियुक्ति व रटने के बजाय समझने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर भी कोचिंग प्रथा को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों का मध्यावधि मूल्यांकन भी मददगार साबित हो सकता है। राज्य बोर्डों को भी छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन को नया स्वरूप देना चाहिए। वे छात्रों को समझ और व्यावहारिक ज्ञान देने को प्राथमिकता दें बजाय कि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की। यदि निजी कोचिंग अपरिहार्य है तो कम आय वाले छात्रों के लिये आर्थिक सहायता नैसर्गिक न्याय करेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना संभव है। अन्यथा कोचिंग का दायरा बढ़ता ही रहेगा। अन्याय असमानता बढ़ेगी और कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी कम होती जाएगी।

राशिफल

मेष :- नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का ऐहशास होगा। जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय की अपेक्षित है। सन्तति एवं सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रयास सार्थक होंगे।
बृषभ:- शासन-सत्ता कें लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य सिद्धि के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ संभव। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।
मिथुन:- कठिन एवं विषम परिस्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति के ओर अग्रसर होंगे। समाजिक सक्रीयता से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घरेलू दायित्वो के प्रति आपकी महत्ता बढ़ेगी।
कर्क:- कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उदेलित करेंगी। निकटस्थ सम्बन्धों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। तामसी व गैर कार्य पर आकर्षित मन पर अंकुश लगावें।
सिंह:- कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत्न क्षेत्रों में संघर्ष संभव परन्तु निराशावादी बिचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित व्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।
कन्या:- नकारात्मक चिन्ताओं को त्याग कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरों-पेशे में अधिकारियों व सहकर्मियों के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनैतिक क्षेत्र के ब्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा।
तुला:- किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लाएगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। दुबिधाओं को त्याग कर सही व स्वच्छ योजनाओं पर केन्द्रित हों।
वृश्चिक:- कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कारये में ब्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के सहयोग से मन उत्साहित होगा।
हंसमुख स्वभाव से आस-पास वातावरण में प्रसन्नता बिखरेंगे।
धनु:- सम्बन्धों में ब्यवहारकुशल बनें। समाजिक व मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी संभव। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता आप में नए उत्साह का संचार करेगा।
मकर:- बिद्यार्थियों के लिए गहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होगी। नवीन आशाएं नवीन उत्साह लाएंगी। कार्य क्षेत्र में सम्बन्धों का भरपूर लाभ मिलेगा।
कुम्भ:- अन्तर्मरुखी स्वभाव को त्याग बहिरमुखी बनें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति के आसार हैं। परिजनों के सुख-दुख के प्रति मन चिन्तित होगा। कार्य क्षेत्र में ब्यस्तता बढ़ेगी।
मीन:- पुरानी समस्याओं पर बिजय प्राप्त कर सुखद अनुभूति करेंगे। गहों की अनुकूलता से कोई अवरोधित कार्य हल होने के आसार बनेंगे। समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन परेशान होगा।



— डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत जैसे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों वाले देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं होता, बल्कि यह परिवार, रिश्तेदार और व्यापक समाज की भागीदारी से जुड़ी एक सामाजिक संस्था है। ऐसे में जब हरियाणा विधानसभा में दादा गौतम ने यह मुद्दा उठाया कि जवान बच्चों की शादी में माँ-बाप की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तो इस पर स्वाभाविक रूप से बहस छिड़ गई। यह बहस केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में हैंकूटनैतिकता, परंपरा, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक

अनुबंध या कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार है। विवाह को परिवारों का मिलन माना जाता है, न कि केवल दो व्यक्तियों का। यही कारण है कि भारत में अधिकांश विवाह आज भी परिवार और समाज की सहमति से ही तय होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के विवाह में केवल निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक होते हैं। उनका अनुभव, सामाजिक पहचान और रिश्तों की समझ विवाह संस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। परंपरा का यह स्वरूप परिवार की इज्जत—आबरू, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की निरंतरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में तेजी से बदलती जीवनशैली और युवाओं की बढ़ती स्वतंत्रता ने विवाह संस्था की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। कई युवा प्रेम विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार की सहमति के बिना विवाह करने के मामले में वृद्धि हो रही है। कई बार ये विवाह सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और पारिवारिक दबाव के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि

यदि हर विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय बन जाए और अभिभावकों की सहमति को दरकिनार कर दिया जाए, तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और रिश्तों की गरिमा पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। अभिभावकों की सहमति के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह परिवार की इज्जत और सामाजिक आबरू को बनाए रखती है। माता-पिता का अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। जीवन की कठिनाइयों, रिश्तों की बारीकियों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ उनसे बेहतर किसी को नहीं हो सकती। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवारों और संस्कृतिियों का मिलन होता है, इसलिए अभिभावकों की सहमति से विवाह में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की संभावना अधिक होती है। जब परिवार पीछे खड़ा होता है तो विवाह का भावनात्मक संतुलन भी मजबूत रहता है। दूसरी ओर विपक्ष में यह तर्क भी उतना ही प्रबल है कि भारतीय संविधान हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का जीवनसाथी चुन सके। किसी भी प्रकार से अभिभावक की सहमति

को बाध्यकारी बनाया व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई बार अभिभावक जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति को ति और रिश्तों की गरिमा पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। उनकी सहमति अनिवार्य कर दी जाए तो यह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अनचाहे विवाह का खतरा भी इसी से पैदा होता है, जहाँ बच्चों पर दबाव डालकर उनकी पसंद के विरुद्ध विवाह कराए जाते हैं। इससे न केवल विवाह असफल होते हैं बल्कि समाज में असंतोष और तनाव भी बढ़ता है। युवाओं की स्वतंत्रता और समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी पसंद के निर्णय लेने का अवसर मिले। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब जातिगत और परंपरागत बंधनों को तोड़कर समानता और आधुनिकता को अपनाया जाए। यह भी सच है कि हर अभिभावक आवश्यक नहीं कि समझदार और प्रगतिशील हो। कई बार उनकी सोच परंपराओं और रूढ़ियों से बंधी होती है, जो बच्चों की स्वतंत्रता और खुशी को आड़े आ सकती है। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में ठोस तर्क हैं।

अभिभावकों की सहमति पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि यह परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। वहीं युवाओं की स्वतंत्रता भी कमतर नहीं आँकी जा सकती, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अतः समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद में है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं, पसंद और स्वतंत्रता को समझें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णय में परिवार की प्रतिष्ठा और अनुभव को महत्व दें। सरकार और समाज की भूमिका यह होनी चाहिए कि वे संवाद और परामर्श को बढ़ावा दें, न कि केवल कानून बनाकर किसी एक पक्ष को बाध्य करें। यदि सरकार इस विषय पर कदम उठाना चाहती है, तो सीधे कानून बनाने की बजाय कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। विवाह के विवादित मामलों में परिवार और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए परामर्श केंद्र बनाए जा सकते हैं। जल्दबाजी और भावनात्मक निर्णयों को संतुलित करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक काउंसलिंग की व्यवस्था हो सकती है। अभिभावकों को समझाने के लिए संवेदनशीलता अभियान चलाए जा सकते हैं।

सकते हैं कि बच्चों की पसंद को नकारना समाधान नहीं है। वहीं युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि वे विवाह को केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझें। दादा गौतम द्वारा उठाई गई चिंता समाज के लिए एक आवश्यक चेतावनी है। अगर विवाह संस्था से परिवार और अभिभावकों की भूमिका पूरी तरह हटा दी गई, तो समाज में नैतिकता और संस्कार कमजोर होंगे। वहीं अगर अभिभावकों की सहमति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, तो युवाओं की स्वतंत्रता पर चोट पहुँचेगी। इसलिए समाधान केवल यही है कि विवाह संस्था को परिवार और अभिभावकों की भूमिका पर आधारित बनाया जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच पारस्परिक सम्मान की वह पुल है, जो परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और संस्कार के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यदि हम इस संतुलन को साध सकें, तो वही विवाह संस्था अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता बनाए रख सकेगी और आने वाली पीढ़ियाँ एक सशक्त, संस्कारित और स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकेंगी।

शूलिनी शोधकर्ता ने प्रमाणित किए हिमालयी पौधों के औषधीय गुण-अस्थमा, बुखार, पीलिया व संक्रमण में उपयोगी



बीएनई

देहरादून। हिमालयी औषधीय पौधे, जिन्हें पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग करते आए हैं, अब वैज्ञानिक रूप से उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रमाणित किए जा रहे हैं। इन पौधों के औषधीय महत्व को अस्थमा, बुखार, पीलिया, शारीरिक दर्द, स्वेदन संबंधी समस्याओं और संक्रमण जैसी स्थितियों के प्रबंधन में कारगर पाया गया है। शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज की सहयोग प्रोफेसर एवं हर्बेरियम व ड्रग म्यूजियम की प्रमारी

डॉ. राधा के व्यापक शोध से पता चला है कि इनमें से कई पौधे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-डायबिटिक, एंटी-कैंसर और यकृत संरक्षण (हेपाटोप्रोटेक्टिव) गुणों से भरपूर हैं। वर्ष 2025 में उन्होंने चार पेटेंट दर्ज कराए हैं, जो पारंपरिक ज्ञान को फलनित फ्यूड और प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों में बदलने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। अध्ययन किए गए पौधों में सेमल के फूल विशेष रूप से आशाजनक पाए गए हैं। पारंपरिक रूप से इनके शीतल और पुनर्स्थापनात्मक गुणों को महत्व दिया जाता रहा है। वैज्ञानिक परीक्षणों में यह फूल आहार फाइबर, फिनॉल्स और फ्लेवोनॉयड्स से भरपूर पाया गया है, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गतिविधियों में सहायक हैं तथा पोषण की कमी को दूर करने में मददगार हैं। इसी आधार पर डॉ. राधा ने सेमल के फूल और सेब से बना पोषक तत्वों से युक्त जैम तथा एक रेडी-टू-सर्व ड्रिंक तैयार की है, जिसमें सभी सक्रिय यौगिक (बायोएक्टिव कम्पाउंड्स) सुरक्षित रहते हैं। इन दोनों उत्पादों में कुत्रिम संरक्षक या रंग का प्रयोग नहीं किया गया है।



से उपयोग होता रहा है, फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉयड्स और ट्राइटरपेनॉयड्स से भरपूर पाया गया। परीक्षणों में इस पौधे के अर्क ने वलेंड्रिस एला न्यूमोनिया और



से प्रसंस्कृत किया गया, जिसमें 13 सक्रिय एंटीमाइक्रोबियल यौगिक सुरक्षित रहे। इन खोजों से आगे बढ़ते हुए, डॉ. राधा के एथनोबॉटैनिकल सर्वेक्षण में 1,600 से अधिक हिमालयी

पौधों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनमें से कई का फाइटोकेमिकल और औषधीय विश्लेषण किया गया। जिसमें प्रवासी गद्दी-बकरवाल चरवाहों द्वारा पशुधन रोगों के उपचार हेतु वैज्ञानिक प्रमाण हैं। इसी प्रकार, गिलोय, जिसका आयुर्वेद में प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक उपयोग होता है, को पर्यावरण-अनुकूल अल्ट्रासोनिक पद्धति



भारतीय जेंटियन (Gentiana kurroo), श्वेत हिमालयी कुमुदीनी (Lilium polphyllum) और हिमालयी जंगली जौ (Elymus himalayanus)

मैदान की नायिकाएँ : ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का उदय

डॉ शिवानी कटारा भारतीय खेल इतिहास लंबे समय तक पुरुष प्रधान रहा, लेकिन बीते कुछ दशकों में महिलाओं ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वह अभूतपूर्व है। कभी खेलों में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ती गई। 2000 के दशक में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग का थी, परंतु आज भारतीय बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परम्व लहरा रही हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों का ओलंपिक प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ता गया है। 2000 में नगण्य उपस्थिति से शुरू होकर यह आँकड़ा आज 40–44% तक पहुँच चुका है। यह बदलाव केवल खेलों का नहीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और बदलती सोच का भी प्रतीक है। कहा जाता है —“भर्तृकन्या स्त्रियः श्रेयो लभन्ते लोकसम्मतम्।” अर्थात् स्त्रियों अपनी निष्ठा और कर्म से लोक में श्रेष्ठ यश प्राप्त करती हैं। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में मैरी डिस्जुा ने भारत का प्रतिनिधित्व कर इतिहास रचा। वे पहली भारतीय महिला

एथलीट थीं जिन्होंने ओलंपिक मंच पर कदम रखा। उस समय न पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ थीं, न ही समाज से उन्हें व्यापक स्वीकृति मिलती थी। धीरे-धीरे समय बदला और 1980 के दशक में पी.टी. उषा भारतीय खेलों का बड़ा नाम बनीं। “ट्रैक क्वीन” कही जाने वाली उषा ने 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में चौथा स्थान पाकर इतिहास रचा। पदक से कुछ सेकंड दूर रह जाने पर भी उन्होंने दिखाया कि भारतीय महिलाएँ ट्रैक पर वैश्विक

बार की विश्व चैंपियन बनीं और राज्यसभा सांसद के रूप में भी सभी को प्रेरणा देती रहीं। 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने देश की उम्मीदों को संभाला। पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में ‘प्रोडुनिया’ जैसे कठिन वॉल्ट को सफलतापूर्वक कर देश को रोमांचित किया। यहीं से यह धारणा और गहरी हो गई कि महिलाएँ

मलिक और मीराबाई चानू को देखकर आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा जैसे राज्यों के छोटे गाँवों से निकलकर बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँच रही हैं। वहीं कभी बेटियों के जन्म पर खुशी तक नहीं मनाई जाती थी। भारतीय महिलाओं का खेल सफर सशक्तिकरण की जीवंत गाथा है। बदलते समाज में परिवार बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों में सुविधाएँ बढ़ी हैं और सरकार ‘खेलो इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों से महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। इस यात्रा से यह सिद्ध होता है कि वास्तविक बदलाव सिर्फ पदकों से नहीं, बल्कि उन संघर्षों से उपजता है जिन्हें खिलाड़ी अपने पीछे प्रेरक उदाहरण के रूप में समाज के लिए छोड़ जाती हैं। पी.टी. उषा की दौड़, कर्णम मल्लेश्वरी का ऐतिहासिक पदक, मैरी कॉम की जुझारू लड़ाई, सिंधु का आत्मविश्वास और मीराबाई का साहसकृत्य सब मिलकर भारतीय महिलाओं की बदलती स्थिति की कथा कहते हैं। जैसा कि मैरी कॉम

ने कहा है‘कभी’ हार मत मानी, क्योंकि जब तुम हार मानते हो, तभी तुम्हरी असली हार होती है।’ आज भारतीय महिला खिलाड़ी केवल पदक नहीं जीत रही, बल्कि रूढ़ियों तोड़कर बेटियों को प्रेरित कर रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि खेल जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है—संघर्ष अनुशासन और आत्मविश्वास। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में भारतीय महिलाओं ने खेलों के दिशा और स्वरूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया।

बिहार में हर घर से उठेगी महिला उद्यमी! नीतीश सरकार ने लॉन्च की ऐतिहासिक योजना

बिहार के हर घर में एक महिला उद्यमी तैयार होगी! जी हाँ, ये कोई गप नहीं है। आज इसकी रूप रेखा और सीएम नीतीश कुमार के इस विजन का ऐलान कर दिया गया है। जो बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ताकत तो देगा ही बल्कि बिहार से पलायन की मजबूरी भी खत्म कर देगा। आज कैबिनेट की बैठक में इस नीति को अमली जामा पहना दिया गया है। हर घर से उद्यमी महिला आएंगी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘युध्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत हर घर से एक महिला को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम को बिहार की महिलाओं के लिए अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है अब कदम से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि हर घर से उद्यमी महिलाएं निकलती नजर आएंगे। 10000 रुपये की पहली किस्त मुफ्त! इस योजना की शुरुआत इसी सितंबर 2025 से हो जाएगी। इसके तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह अनुदान के रूप में होगा। जिसे रोजगार करने वाली महिलाओं को लौटाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। रोजगार शुरू करने के छह माह बाद उनके काम का आकलन किया जाएगा। यदि वो एक सफल उद्यमी के बनने में सफल हुई तो ऐसी महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी दी जा सकेगी। ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी इस योजना के सफल संचालन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट—बाजार विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। जिसका फायदा उद्यमी महिलाओं को सीधे तौर पर मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदमरूप सीएम नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा महत्त्वपूर्ण होने वाला है। यह योजना अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि “हर घर से एक महिला उद्यमी तैयार होगी तो बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी और पलायन की मजबूरी भी कम होगी।”



संभल हिंसा पर सीएम योगी का कड़ा बयान

कहा डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों को खुद होगा पलायन

संवाददाता

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट के बाद अपने पहले बयान में साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसी भी इलाके की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) को नहीं बदलने देगी। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद ही पलायन करना पड़ेगा। अब यह बयान यह दर्शाता है कि योगी सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपना रही है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर



जीआईसी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर

प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश की जनसांख्यिकी को बदलने नहीं देगी। उन्होंने साफ किया कि अब कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे प्रदेश या जिले से पलायन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि योगी सरकार ने इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस का निर्णय लिया है। सीएम ने यह भी कहा कि अब शासन बिना किसी भेदभाव के चलता है। अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के जरिए सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की नीति पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ को करीब 550 करोड़ रुपये की 116 नई परियोजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपी गईं। छात्र सम्मान में सीएम ने कई विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए। यही नहीं योजना के तहत लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपए

संक्षिप्त

केसे ध्यान सिंह बने ध्यानचंद? देश मना रहा 120वीं जयंती; हॉकी के जादूगर के बारे में 10 बातें

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने तीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में उनके रहते हुए टीम ने कमाल किया था और स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। उनकी गोल करने की क्षमता के आगे विपक्षी टीम बेबस नजर आती थी। वह सिर्फ दूसरे छोर से ध्यानचंद को देखते ही रह जाते थे। हॉकी में ध्यानचंद को वही मुकाम हासिल है, जो क्रिकेट में डॉन ब्रेडमैन



को और फुटबॉल में पेले को है। आज शुक्रवार (29 अगस्त 2025) को रहींकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे ध्यानचंद की जयंती पर हर साल देश में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में हम आपको 10 अनोखी बातें बता रहे हैं... ध्यानचंद 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद काफी अभ्यास किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता। इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उनके नाम के आगे श्वंदर लगा दिया। असल में ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। 1928 में एम्सटर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उस

संक्षिप्त

एक समान कारोबार में एनबीएफसी की सहायक कंपनियां नहीं कर सकेंगी व्यापार, रोजाना लाने पर काम कर रहा आरबीआई

एजेंसी

मुंबई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की सहायक इकाइयां अब समान कारोबार में शामिल नहीं हो पाएंगी। आरबीआई जल्द ही इस तरह की योजना लाने पर काम कर रहा है। बैंकों के लिए यह नियम पहले से ही लागू हैं। अब एक ही कारोबार में दो कंपनियों के शामिल होने के टकराव को रोकने के लिए एनबीएफसी को भी इस दायरे में लाया जाएगा। सूत्रों ने बताया, आरबीआई कुछ एनबीएफसी के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। दिशानिर्देश जल्द जारी होने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक इस क्षेत्र में संभावित उथल-पुथल के प्रति सतर्क रहा है। उसने एनबीएफसी को चेतावनी दी है कि वह बेतहाशा कर्ज बांटने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। आरबीआई को चिंता है कि ज्यादा ग्राहक लाने के लिए नकली कारोबार जैसी प्रथा जटिल ऋण संरचना को जन्म दे सकती है। इससे जोखिम बढ़ सकते हैं। एनबीएफसी के आक्रामक कर्ज देने से बड़ी चिंता सूत्रों ने बताया, आरबीआई का नया निर्देश मुख्य रूप से बड़ी गोल्ड फाइनंस कंपनियों को प्रभावित कर सकता है। इनकी सूक्ष्म वित्त शाखाएं गोल्ड लोन देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग ने जमकर कर्ज बांटे हैं। इस आक्रामक विस्तार के कारण नियामक ने कड़ी कार्रवाई भी की है। इसके बाद ही एचडीएफसी और एक्सिस जैसे कई बैंकों को अपनी उपभोक्ता ऋण सहायक कंपनियों को खरीदने के लिए साझेदारों की तलाश करनी पड़ी है।

उर्जित पटेल को आईएमएफ में बड़ी जिम्मेदारी

आरबीआई गवर्नर के रूप में किया था शानदार काम

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एजीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर उनके कार्यकाल को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी। अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की सहमति के बाद उर्जित पटेल को इस बेहद महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया और केंद्र सरकार के 28 अगस्त के नोटीफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल सितंबर 2019 तक था, लेकिन इसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वे एनआईपीएफपी के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं।



पहली तिमाही में आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रह सकती है वृद्धि दर, खपत और मांग से तर होगा भविष्य

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में आरबीआई के 6.5 फीसदी के अनुमान से ज्यादा रह सकती है। वहीं, अन्य एजेंसियों ने वृद्धि दर इससे ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। इटका ने



पहली तिमाही के लिए 6.7 फीसदी का अनुमान दिया है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान 6.8 से 7 फीसदी तक का है। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक, पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.7 फीसदी रह सकती है।

सरकार पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े शुक्रवार को शाम पांच बजे जारी करेगी। अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने के बाद पहली तिमाही के मजबूत आंकड़ों से बाजार पूरे वित्त वर्ष की तस्वीर देखने की कोशिश करेगा। जीडीपी आंकड़ों में खास नजर निजी खपत और मांग पर होगी। वर्तमान स्थिति में यह देखना पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा सरकारी पूंजीगत खर्च में सालाना 52 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि ने पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। इस खर्च ने नौकरियों के सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग सामानों की मांग को प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च 2.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। यह वृद्धि निजी क्षेत्र की निवेश में कमी को संतुलित करने में महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण मांग और कृषि में सुधार की उम्मीद ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में उछाल से शहरी मांग की कमजोरी संतुलित होने की उम्मीद है। अनुकूल मानसून और रिकॉर्ड फसल उत्पादन से ग्रामीण आय बढ़ी है, जिससे एफएमसीजी, कृषि उपकरण और ग्रामीण खुदरा क्षेत्र में तेजी आ सकती है। टैरिफ का आगे दिख सकता है असर पहली तिमाही टैरिफ से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है, इसलिए अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन मजबूत रह सकता है। दूसरी तिमाही से पूरा असर होगा।

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ के कारण अगले छह महीने में भारत के कपड़ा निर्यात का करीब एक चौथाई हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका भारत के कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और निर्यातक ऑर्डर रह जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। 2024-25 में कपड़ा और परिधान क्षेत्र का आकार 179 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसमें 142 अरब डॉलर का घरेलू बाजार और 37 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा, हम अगले छह महीनों में कम-से-कम 20-25 फीसदी की गिरावट की आशंका देख

नीरज खिताब से चूके, 85.01 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहे वेबर बने विजेता

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बहुत जल्द एशिया कप में खेलते नजर आएंगे। नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी टूर्नामेंट के लिए उन्हें भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। गिल ने अपने वनडे करियर की शुरुआत बेहद प्रभावशाली अंदाज में की है। उन्होंने शुरुआती 55 वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। गिल ने कोहली-सचिन को पछाड़ा भारतीय क्रिकेट में हमेशा से ही युवा खिलाड़ियों की तुलना दिग्गजों से की जाती रही है। शुभमन गिल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर... ये तीनों नाम आज की पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक क्रिकेट



रूप से चर्चा कर रहे हैं। दोनों मंत्रालयों से सहयोग का आश्वासन मिला है। कपास पर केंद्र के फैसले से मिलेगी राहत विशेषज्ञों का कहना है, कपास के शुल्क मुक्त आयात को तीन महीने बढ़ाने से घरेलू कपड़ा उद्योग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। चटर्जी ने कहा, हम बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पहले दी गई छूट से कपास के लिए दिए जाने वाले नए ऑर्डरों पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसे भेजने में कम से कम 45-50 दिन लगते हैं। अब अपेक्षाकृत त लंबी छूट से नए ऑर्डरों पर लाभ होगा। हीरा पॉलिश 30 फीसदी तक घटेगी कमाई 50 फीसदी टैरिफ से देश के प्राकृतिक हीरा पॉलिश उद्योग का चालू वित्त वर्ष में राजस्व 28-30 फीसदी कम होकर 12.50 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। 2024-25 में

आठ शतक और 2775 रन... शुरुआती 55 वनडे मैचों में बनाए सर्वाधिक रन विराट और सचिन को पछाड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बहुत जल्द एशिया कप में खेलते नजर आएंगे। नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी टूर्नामेंट के लिए उन्हें भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। गिल ने अपने वनडे करियर की शुरुआत बेहद प्रभावशाली अंदाज में की है। उन्होंने शुरुआती 55 वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। गिल ने कोहली-सचिन को पछाड़ा भारतीय क्रिकेट में हमेशा से ही युवा खिलाड़ियों की तुलना दिग्गजों से की जाती रही है। शुभमन गिल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर... ये तीनों नाम आज की पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक क्रिकेट



खास बात यह है कि गिल ने इस दौरान आठ शतक भी जड़े हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता का प्रमाण है। वहीं,

लिस्ट में तीसरे स्थान पर क्रिकेट के भागवान सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने शुरुआती 55 पारियों में 1556 रन बनाए थे। उनका औसत 31.76 रहा और इस दौरान उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। हाशिम अमला और इमाम-उल-हक पीछे छूटे अब बात करते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड की तो गिल ने हाशिम अमला और इमाम-उल-हक जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। वनडे की शुरुआती 55 पारियों में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला हैं। अमला ने शुरुआती 55 मैचों के बाद 54 पारियों में 2713 रन बनाए थे। उनका औसत 55.37 का रहा और उन्होंने नौ शतक जड़े थे। वहीं, पाकिस्तान के इमाम-उल-हक ने शुरुआती 55 मैचों की 55 पारियों में 2539 रन बनाए थे।